ted by the Kendriya Vidyalaya Sangathan in such a way that certain categories of employees including PGTs, on promotion are denied posting in—

— the State in which pre-promotion station is located as well as

— the State of domicile of the concerned employee.

In fact, as per correct interpretation of this rule, promotional postings to State of domicile—so long as that State in other than the State of pre-promotion posting should not devided.

The Kendriya Vidyalaya Sangathan does not consider it appropriate to provide for promotion to posts involving managerial duties including to posts of Vice-Principals on the basis of mere seniority-cum-fitness.

The Kendriya Vidyalaya Sangathan agrees with the interpretation that promotional posting can be to a State of domicile so long as it is a State other than the State of pre-promotion posting—subject to availability of vacancy;

Regularisation and continuation of jobs of NCC Officers

1767. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cases of some NCC Officers who have completed 50 years of age after 13th February, 1987, are being considered by the Centre for regularisation and for continuation in the jobs;

(b) if so, what is the number of such NCC officers; and

(c) by when Government are likely to finalise the case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) Yes, Sir.

(b) 171 Officers.

(c) No definite time schedule can be given.

Deprivation of the retried Defence Officers of the membership of Defence Services Officers Welfare Institute

1768. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the retired officers of Defence have been deprived of membership of the Defence Service Officers' Welfare Institute; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. RAJA RAMANNA): (a) and (b) The Defence Service Officers Institute, Dhaula Kuan is not a Government Organisation. The Institute is administered according to its own rules and regulations by its own governing body. Retired Services' officers as a class have not been deprived of their membership of the Institute.

अन्तरिक्ष विभाग द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी शुरू किया गया कार्यक्रम

1769. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष विभाग द्वारा ग्रामीण लोगों के निर्वाह संबंधी दशाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से 1990–95 के वर्षों के लिए एक कार्य-योजना शुरू की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य-योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्य-योजना से कुल कितने ग्रामीण लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री साथ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में अतिरिक्त प्रभार (प्रो० एम० जी० के० मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्धनता को कम करने, भूमि उपयोग और जल संसाधन प्रबन्ध पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य-योजना के भाग के रूप में शुरू की जा रही विविध परियोजनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

- आपदा प्रबन्ध और संचार के लिए इन्सैट सेवाएं
- राष्ट्रीय कृषि सूखा आंकलन
- सूखे के मुकाबले के लिए समाकलित उपागम
- बाढ़प्रवण क्षेत्र का मानचित्रण तथा क्षति का आकलन
- रेगिस्तानी टिड्डी प्रवास का मानीटरन
- कृषि-जलवायवी क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग/आवरण मानचित्रण
- फ़सल का एकड़वार और पैदावार आंकलन
- राष्ट्रव्यापी मृदा लवणता/क्षारीयता मानचित्रण
- परतीभूमि मानचित्रण
- राष्ट्रीय वन आवरण मानचित्रण
- राष्ट्रव्यापी चरागाह भूमि मानचित्रण
- उत्तर-पश्चिम भारत में रेगिस्तान का मानीटरन
- खनन का पर्यावरणीय प्रभाव
- भूमिगत कोयला अग्नि का मानीटरन और संसूचन
- शहरी विस्तार मानचित्रण
- वन्य-जीवन वास आकलन
- माइक्रोवेव आंकड़ों का उपयोग करते हुए मृदा आर्द्रता आकलन
- शहतूत की फ़सल की तालिका
- अन्तर्देशीय मत्स्यपालन के लिए तटीय नम भूमि का मानचित्रण
- समुद्री मत्स्यपालन के संभावित क्षेत्रों का निर्धारण
- भूमिजल संभाव्यता क्षेत्र का मानचित्रण
- जलाशयों के सतही जल का मानीटरन
- ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जल-विभाजकों का प्राथमिकीकरण
- कमाण्ड क्षेत्रों में जल प्रबन्ध
- बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं (नर्मदा, टिहरी और शान्त घाटी) के पर्यावरणीय प्रभाव
- लघु/माइक्रो जलविद्युत के लिए स्थल निर्धारण
- हिम-गलन प्रवाह तथा जलाशयों में जल प्रवाह
- सुदूर संवेदन प्रशिक्षण और शिक्षा
- राज्य सुदूर संवेदन केन्द्रों की स्थापना (चालू परियोजना)
- अंकीय भूभाग माडलिंग
- जिला/ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय संसाधन सूचना प्रणाली (एन०आर०आई० एस०) विकास

(ग) उपर्युक्त इन सभी उपयोग परियोजनाओं का उद्देश्य चरणबद्ध रूप में सम्पूर्ण देश को आवृत्त करना है।

देश में परमाणु प्रतिष्ठानों में विकिरण के प्रभाव से असामान्य वृद्धि

1770. **श्री राम नरेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 मार्च, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "रेडिएशन एक्सपोजर टू हाई: ए०ई०आर० बी०" शीर्षक के अन्तर्गत छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में लगभग सभी परमाणु प्रतिष्ठानों में विकिरण के कुल प्रभाव में असामान्य वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और